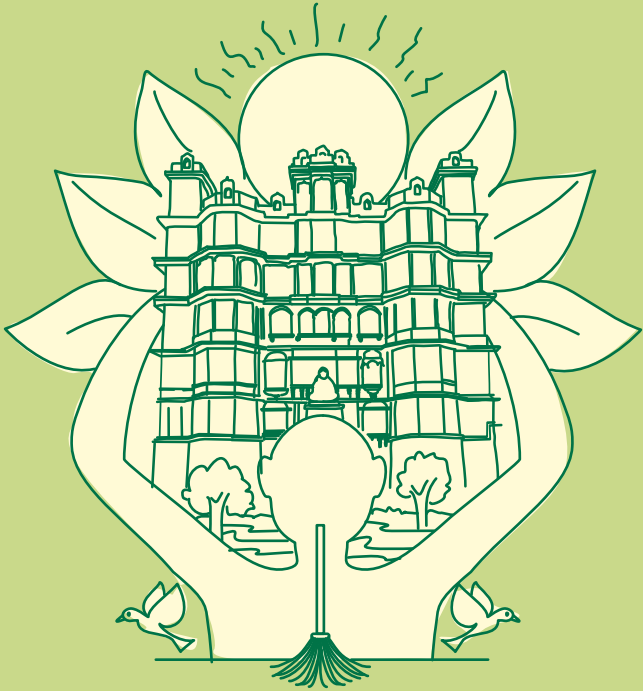


हमारा इन्दौर हमारा पर्यावरण



परिदृश्य और
चुनौतियाँ



विश्व पर्यावरण दिवस-2023



मध्यप्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के रूप में इन्दौर की अपनी विशिष्ट पहचान है। इसके अलावा सांस्कृतिक हलचल के लिए भी यह शहर जाना जाता रहा है। लेकिन जो बात इसे पूरे देश में विशिष्ट बनाती है वह है सामाजिक सरोकार का ऐसा ताना-बाना जो बदलते समय के बावजूद अप्रभावित रहा है। सेवा-सुरभि ने समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों को हाथ में लेकर यह साबित किया है कि इस शहर के नागरिक पूरी संजीदगी से अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति सजग हैं। संस्कृति, प्रकृति और राष्ट्रप्रेम पर एकाग्र इसकी गतिविधियों ने शहर में खास प्रतिमान स्थापित किये हैं। गणतंत्र दिवस के अंतर्गत आयोजित झण्डा ऊँचा रहे अभियान ने सेवा-सुरभि को देशव्यापी पहचान/प्रशंसा दी है. पर्यावरण और खासकर हरियाली के लिए किए गये सुकार्यों को सर्वत्र सराहा गया है. इन्दौर शहर की सामाजिक ज़रूरतों और समस्याओं के प्रति भी संस्था सदैव सचेत और सजग है. श्रेय की कामना से परे सेवा-सुरभि का सफ़र अब रजत पथ यानी अपनी स्थापना की पच्चीस वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है. हम एक छोटा सा समूह हैं किंतु हमारी सामाजिक चिंताएँ सबको जोड़कर चलने और एक समवेत स्वर बनने में यकीन रखती है. श्रेय की राजनीति से परहेज़ रखते हुए सेवा-सुरभि चाहती है कि उसके काम की खुशबू जन-जन के मन में उतरे और सर्वत्र महके.



राष्ट्रप्रेम



प्रकृति



संस्कृति



49 अग्रवाल नगर (पुरानी भूमि) इन्दौर - 452 001

मोबाइल : 099931-52000, 094250-58180

ई-मेल : sevasurabhiindore@gmail.com

प्रकाशन : विश्व पर्यावरण दिवस 2023



हमारी बात

सेवा-सुरभि अपनी रजत यात्रा की ओर अग्रसर है. भारत की आज़ादी के अमृतकाल के दौरान आ रहा रहा विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश आर्थिक और सामरिक परिदृश्य पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है. हमारी प्रतिभाएँ पूरे विश्व में एक मुकम्मल पहचान रखती हैं. आवश्यक हो गया है कि देश का हर शहर इस गर्वोक्ति के साथ कि हम एक महाशक्ति हैं अपने हवा-पानी, जंगल-जीव, भूजल और तापमान के परिवर्तनों के प्रति भी सतर्क रहे. सूचना क्रांति का लाभ पर्यावरण क्षेत्र को भी मिला है. तमाम प्रगति और विकास के आलम में हम अपने शहरों, गाँवों और मनुष्य के स्वास्थ्य के प्रति भी बाखबर रहें.

कोरोना महामारी का सामना करते हुए हमने तत्परता और गंभीरता से पूरी दुनिया को चकित किया. कई देशों के कोविड उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वैक्सीनेशन को लेकर भी हमने मिसाल कायम की. यही तत्परता, सक्रियता, ज़िम्मेदारी का भाव पर्यावरण

के लिए भी जगाना पड़ेगा. आम आदमी, नगरीय निकाय, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के स्तर पर ऐसा एक चाकचौबंद सिस्टम ईजाद करना होगा जिससे पेड़, पानी, हवा, भू-जल के प्रति सजगता का भाव बने. औद्योगिक प्रदूषण और धरती के बढ़ते तापमान के प्रति हमें निरंतर सतर्क रहना होगा. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निस्तारण की कठोर रीति-नीति तय करनी होगी. पानी के अपव्यय के प्रति जन-जन में जागरुकता लानी होगी. यह भी देखना होगा कि विकास और टेक्नोलॉजी के साए में हम जिन सुविधाओं का ताना-बाना बुन रहे हैं, वे हमारे लिए कहीं भस्मासुर न बन जाएँ.

सेवा-सुरभि इन्हीं भावनाओं और चिंताओं के साथ यह पुस्तिका आपके हाथों तक पहुँचाते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रही है. विगत वर्षों में समाचार पत्रों में प्रकाशित हवा, पानी, हरियाली, स्वच्छता और ध्वनि प्रदूषण पर एकाग्र समाचारों और आलोखों के संपादित अंशों का हमने इस प्रकाशन में संकलित किया है. आप चाहें तो इसे इन्दौर के पर्यावरण का सिंहावलोकन या श्वेत पत्र भी कह सकते हैं. इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री के लिए हम सभी मीडिया संस्थानों का आभार

प्रकट करते हैं. हमारा संकल्प था कि पर्यावरण को लेकर प्रकट की गई वस्तु स्थितियों, चेतावनियों और सुझावों को एक जगह सहेजा जाए जिसे शोधार्थी, पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठन संदर्भ के रूप में उपयोग में ले सकें.

हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना सिर्फ शासन-प्रशासन का ही दायित्व नहीं, उसके लिए आम आदमी को भी आगे आना होगा. जिस शहर में हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं या कारोबार कर लाभ अर्जित करते हैं, उसके हवा-पानी हरियाली को भी हमें अपनी चिंताओं में शामिल करना होगा. विश्व पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता तभी सिद्ध होगी जब हम सब मिलकर सोचेंगे कि मुफ्त में मिल रही हवा, सूरज की रौशनी, नदियों का जल और जंगलों से मिलती ऑक्सीजन हम सबके लिए प्रकृति प्रदत्त अनूठी सौगातें हैं. यह प्रकाशन पर्यावरण जागरूकता का एक सार्थक संदर्भ बन सके. इसी अपेक्षा के साथ हम मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय संबंधों की कामना करते हैं.

सामग्री संचयन:

डॉ. ओ.पी.जोशी

सुधीन्द्र मोहन शर्मा

डॉ. किशोर पँवार

भोलेश्वर दुबे

संयोजन:

ओमप्रकाश नरेडा, कुमार सिद्धार्थ, संजय पटेल



हवा

शुद्ध हवा से बढ़ जाएगी इंदौरियों की उम्र



भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में शीर्ष पर है। इस वजह से हर भारतीय का औसत जीवन काल 6.3 वर्ष कम हो जाता है। कई रिसर्च बताती हैं कि दुनिया की 95 प्रतिशत आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है। यह आम धारणा है कि वायु प्रदूषण केवल उत्तर भारतीय शहरों विशेषकर दिल्ली की समस्या है। इंदौर के लिए एयर क्वालिटी लाइफ़ इंडेक्स 4.9 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि यदि वायु गुणवत्ता पर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को पूरा किया जाता है तो इन्दौरियों की उम्र 4 साल 9 माह तक बढ़ सकती है।

शिशु मृत्युदर 10% बढ़ी

इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और डब्ल्यूएचओ द्वारा एयर क्वालिटी को लेकर नई गाइड लाइन के तहत बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। इसमें बताया गया कि वायु प्रदूषण निमोनिया को बढ़ाता है। इंदौर में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में 10% वृद्धि देखी गई है।

लेखा नहीं यह आज का,
कहती वेदों की वाणी
प्रकृति की समृद्धि से ही,
सुख पाऊँगे सारे प्राणी



दूषित वायु से बढ़ रहे हैं अस्थमा के मरीज़

प्रदूषित क्षेत्रों में अस्थमा बीमारी से प्रभावित बच्चों की बढ़ती संख्या चुनौती बनी हुई है। वाहनों की अधिक आवाजाही तथा औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास की जगहों में यहाँ के बच्चों में इसका अधिक प्रभाव नज़र आता है। दो-तीन साल की उम्र में ही बच्चों में इस बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में इसके प्रति समुचित जागरूकता नहीं है। अस्थमा को पहले बुज़ुर्गों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब सभी आयु वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। उन बच्चों में यह बीमारी फैलने का खतरा अधिक होता है, जिनके माता-पिता को पूर्व में भी किसी तरह की एलर्जी रही है।



हर शख्स गुनाहगार है
'कुदरत' के क़त्ल में,
ये हवाएँ ज़हरीली
यूँ ही नहीं हुईं

इंदौर में है 12 प्रतिशत लोगों को अस्थमा

बढ़ते प्रदूषण और खानपान के बदलाव से अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ी है। शहर में अभी 12% लोगों को अस्थमा है। हर साल मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शासकीय अस्पताल की ओपीडी में भी प्रतिदिन करीब 100 मरीज श्वसन रोग के आते हैं इनमें से करीब 20 मरीज अस्थमा के होते हैं। लोग समय पर इसका इलाज भी नहीं करवाते हैं। कई लोग बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। इससे यह बीमारी बड़ा रूप ले लेती है।



नीचे गिरे सूखे पत्तों पर
अदब से चलना ज़रा
कभी कड़ी धूप में तुमने
इनसे ही पनाह माँगी थी

सांसों में हर दिन घुलता ज़हर

देश के सबसे स्वच्छ शहर की वायु गुणवत्ता खराब है। प्रतिदिन इसकी पुष्टि हो रही है। इसके बावजूद ज़िम्मेदार विभाग खानापूति कर नाकाम साबित हो रहे हैं। उधर, हर दिन शहरवासियों की सांसों में ज़हर घुल रहा है। प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए संयंत्र लगाए जा रहे हैं, लेकिन खराब आबोहवा को सुधारने की दिशा में काम नहीं हो रहा है। शहर की वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रही संस्था क्लीन एयर कैटलिस्ट ने भी इस बारे में चिंता जताई है। इंदौर देश के उन 37 शहरों में शामिल है, जहाँ पाँच वर्षों में वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज हुई है।

रिसर्च में सामने आया है कि वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, कचरा, बायोमास जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। शहर का सालभर का एक्यूआइ औसतन 100 से अधिक बना हुआ है।

किसे-क्या करना था

- **प्रदूषण नियंत्रण विभाग :** प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती नहीं। करीब 170 उद्योग लकड़ी, कोयला, एग्रो ब्रिकेट से चल रहे हैं।
- **परिवहन विभाग :** पुराने वाहन मानक स्तर से ज़्यादा धुआँ उगल रहे हैं।
- **नगर निगम :** निर्माण कार्यों से फैल रही धूल-मिट्टी को लेकर सख्ती नहीं। सड़कों की नियमित सफाई नहीं।
- **कृषि विभाग :** पराली जलाने पर ध्यान नहीं।

जिन शहरों की निगरानी की जा रही है उनमें इंदौर भी शामिल है। वायु प्रदूषण के कारण सांस की गंभीर बीमारियों, हार्ट अटैक आदि का खतरा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंदौर को नॉन अटेनमेंट सिटी का दर्जा देते हुए वायु प्रदूषण स्तर को कम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।

देश के स्वच्छतम शहर में पैर फैला रहा है प्रदूषण

सफाई में छह बार नंबर 1 का तमगा हासिल करने के बाद नगर निगम का सारा ज़ोर वायु की गुणवत्ता सुधारने पर है। गंगवाल बस स्टैंड, चोइथराम सब्ज़ी मंडी, पोलोग्राउंड, पलासिया चौराहा, इमली बाज़ार, जवाहर मार्ग, साँवेर रोड, भँवरकुआँ, कोठारी मार्केट, रेलवे स्टेशन, छप्पन दुकान, राजबाड़ा, विजय नगर, पीपल्याहाना कुछ ऐसे हॉट स्पॉट हैं, जहाँ वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। इन इलाकों में एयर क्वालिटी की जाँच के लिए मशीनें या उपकरण नहीं हैं। ये वे क्षेत्र हैं, जहाँ या तो भारी यातायात का दबाव है या कोई औद्योगिक संस्थान है। इन क्षेत्रों में निगम का ज़ोर धूल के कण साफ करने पर है। कचरा और फूड वेस्ट भी इन बाज़ारों को प्रदूषित कर रहे हैं।

ये हैं प्रदूषण के नए हॉट स्पॉट

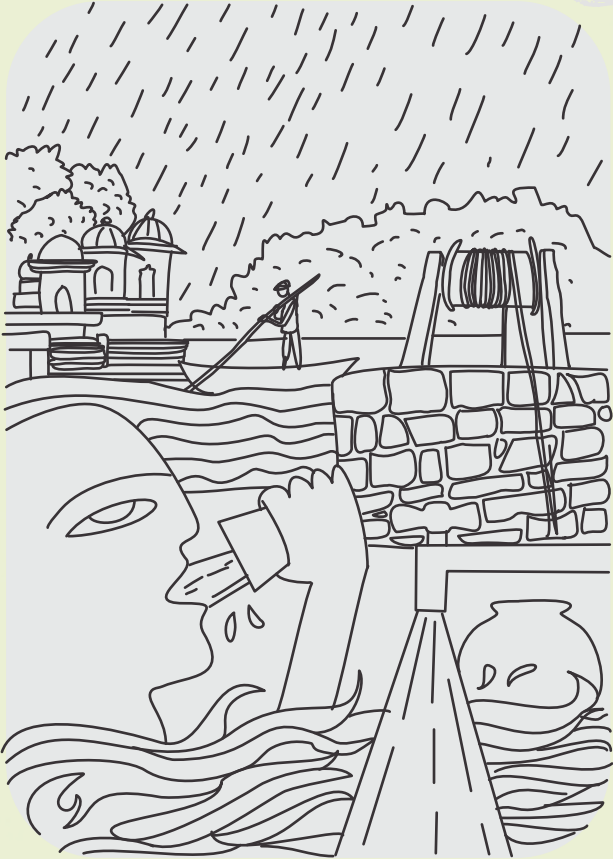
- **चाट-चौपाटी** - सराफ़ा बाज़ार, छप्पन दुकान
- **इंडस्ट्री** - पीथमपुर, साँवेर रोड, पोलोग्राउंड, लक्ष्मीबाई नगर, पालदा, औद्योगिक क्षेत्र
- **कंस्ट्रक्शन साइट** - बंगाली चौराहा, पीपल्याहाना, निपानिया
- **ट्रैफिक लोड** - महु नाका, जवाहर मार्ग, कोठारी मार्केट, भँवरकुआँ, इमली बाज़ार

इंडस्ट्री, चौराहे, चाट-चौपाटी
पर बढ़ता प्रदूषण;
AQI का स्तर 151 पर
लक्ष्य - इसे 50 पर लाना



प्यारी सी नदियाँ बहती थीं ।
वृक्ष जहाँ झूमते रहते थे ।
आज वहाँ कंकर पत्थर हैं
वृक्ष बदल गए आज ठूँठ में
हर मानव के कर्म हैं कैसे
आज नहीं समझते हम ।
कल न रहेगा सुरक्षित पर्यावरण
कल न रहेंगे 'मानव' हम ।

-आशुतोष सिंह गौर



पानी

एक सुखद खबर...

बढ़ रहा है भूजल का स्तर

भविष्य में नर्मदा के अलावा स्थानीय जल स्रोतों के रखरखाव एवं उनसे आपूर्ति पर ध्यान देना होगा।

स्वच्छता के बाद भूजल स्तर को बचाने में भी इंदौर ने बड़ा काम कर दिखाया है। वर्ष 2020 तक अतिदोहित भूजल करने वाला इंदौर 26 फीसदी से भी ज़्यादा ज़मीन का पानी बचाकर क्रिटिकल श्रेणी में आ गया है, जो बड़े शहरों के लिहाज़ से बेहतर है। इंदौर में अब भूजल दोहन 90 से 100 फीसदी के बीच है, जो 8 साल पहले 137 से 140 फीसदी तक था।

वर्ष 2022 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सबसे अहम बात ये है कि इंदौर ने उस शहरी क्षेत्र में पानी कम दोहन किया है, जहाँ वह सबसे ज़्यादा दोहित क्षेत्रों में चिह्नित होता आ रहा था। इसकी वजह से शहर के कई इलाकों में भूजल स्तर 600 से 800 फीट नीचे चला गया था। अब ताज़ा रिपोर्ट के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि शहर के कई क्षेत्रों में 50 से 100 फीट तक पानी कम गहराई पर मिलने लगेगा।

नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर का भूजल स्तर औसत 103 मीटर से घटकर 20 से 40 मीटर के बीच पहुँच गया है। अलग-अलग इलाकों में लगे पीज़ोमीटर से ये आंकड़े सामने आए हैं।

गर्मी से पहले राहत की खबर, ज़मीन का 26% पानी बचा-इंदौर अतिदोहित क्षेत्र से बाहर, कई क्षेत्रों में 100 फीट के अंदर भूजल

इंदौर की सफलता के कारण:

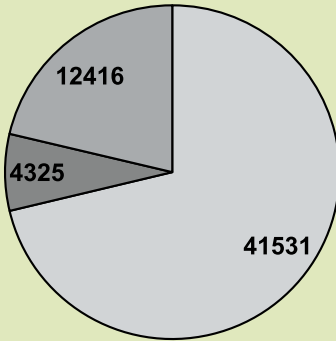
35% तक इलाकों में ही ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं। चार साल पहले शहर का 45% इलाका ट्यूबवेल पर निर्भर था, नर्मदा सप्लाय का क्षेत्र बढ़ने से यह संभव हुआ।

15% वर्षा जल पहले से मुकाबले ज़मीन में पहुँचने लगा। 5 साल में 1 लाख घरों, इमारतों, दफ्तरों में वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने से यह संभव हुआ।

2007 से लगातार बारिश औसत या उससे अधिक हो रही। हर साल 40 इंच पानी बरस रहा है जिससे शहर का भूजल स्तर सुधर रहा है।

5% तक पानी का दुरुपयोग भी कम हुआ। यह शहर में सफाई के प्रति जागरूकता के कारण यह संभव हो पाया।

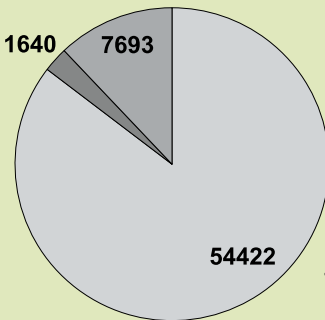
इन्दौर जिले में भूजल रीचार्ज



- Recharge from Rainfall
- Recharge from other sources in Monsoon
- Recharge From other sources in non monsoon season

कुल रिचार्ज = 58272 HaM
1 HaM = 1 करोड़ लीटर

इन्दौर जिले में भूजल उपयोग



- सिंचाई
- औद्योगिक
- घरेलू उपयोग

कुल भूजल उपयोग = 63755 HaM
1 HaM = 1 करोड़ लीटर

इन्दौर ज़िले में भूजल संतुलन (2022)

वर्षाजल द्वारा	मानसून में अन्य स्रोतों से	गैर मानसून काल में अन्य स्रोतों से	कुल रीचार्ज	प्राकृतिक रिसाव	कुल भूजल उपलब्धता
41531	4325	12416	58272	5272	52999

	कृषि उपयोग	घरेलू उपयोग	औद्योगिक उपयोग	कुल उपयोग
भूजल उपयोग	54421	7693	1640	63755

1 HaM = 1 करोड़ लीटर

इन्दौर ज़िले में भूजल संतुलन-2

कुल भूजल उपलब्धता	कुल भूजल उपयोग	कुल अति दोहन	अनुमानित घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग - 2025	कृषि के लिए उपलब्ध भूजल 2025
52999	63755	120.29%	8966	-12208

- कृषि के लिए आवश्यकता : 65109 HaM
- कृषि के लिए उपलब्ध : 54421-8966 = 45455 HaM
- कृषि के लिए कुल उपलब्धता : 45455-54421 = -8966 HaM
- कृषि में पानी की खपत में 8966 HaM की कमी करनी होगी (16.47%)



उतना ही गिलास भरें
जितना पीना हो पानी
जल के खूब होते ही,
नहीं है जिन्दगानी

तिल-तिलकर मर रही, इंदौर की लाइफ लाइन

स्वच्छता में नंबर वन का खिताब हासिल करने वाले इंदौर को भले ही देश का पहला वॉटर प्लस शहर घोषित किया गया है लेकिन, शहर के भूमिगत जल आधार माने जाने वाली कान्ह और सरस्वती नदी अभी भी दूषित है। इंदौर की मुख्य नदी कान्ह और सरस्वती के शुद्धिकरण पर बीते 15 सालों में नगर निगम 1157 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं, 511 करोड़ और खर्च करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। 1668 करोड़ की यह राशि खर्च होने के बाद भी नदी साफ होगी या नहीं इसको लेकर संशय है।

नगर-निगम बीते 15 सालों में जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास मिशन (जेएनएनयूआरएम), सिंहस्थ-2016 मद, स्मार्ट सिटी, अमृत-1 और नाला टेपिंग की बड़ी-बड़ी योजनाओं के ज़रिए नदियों की सफाई पर पैसा खर्च करती रही है। इन सभी योजनाओं पर अभी तक 1157 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके

अलावा भी नदी सफाई के लिए कई बार छोटे-बड़े स्तर पर काम किया गया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ के आसपास खर्च हो चुका है। इसके बाद में भी नदी में लगातार गंदा-काला पानी बना हुआ है। वहीं, अब नदी में पानी पहुँचाने वाली सहायक नदियों पर 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने के लिए “नमामी गंगे प्रॉजेक्ट” के तहत केंद्र सरकार ने 511 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं। इससे कबीट खेड़ी में 120 एमएलडी, लक्ष्मीबाई प्रतिमा के पास 35 एमएलडी और कनाड़िया में 40 एमएलडी का एसटीपी प्लांट बनाया जाएगा। यहाँ से साफ हुआ पानी के पुर्नउपयोग के लिए 13 किमी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये पैसा भी इंदौर नगर निगम को मिल चुका है। इन एसटीपी के बनने से नदी में केवल साफ पानी ही बहेगा, इसकी गारंटी फिलहाल कोई नहीं ले रहा है।

कान्ह और सरस्वती नदी का पुराना वैभव लौटाने के लिए और इसके साफ सफाई पर भविष्य में 2025 तक अगले 2-3 सालों में ठोस और ईमानदार प्रयासों की ज़रूरत होगी ।

हमारी कान्ह अब 'नमामि गंगे मिशन' का हिस्सा

इंदौर की कान्ह नदी अब राष्ट्रीय गंगा संरक्षण मिशन का हिस्सा होगी। केंद्र सरकार ने इसे 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' में शामिल करते हुए 511 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत 195 एमएलडी के तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे।

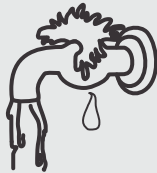
शहरी सीमा से सटे गाँव व शिप्रा शुद्धिकरण के लिए इस परियोजना को मंजूरी मिली है। 244 करोड़ रुपए एसटीपी के निर्माण और 190 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे। दो साल में काम पूरा किया जाएगा। इसमें एसटीपी के जरिये कान्ह नदी का पानी साफ किया जाएगा और फिर उसे शिप्रा में छोड़ेंगे। इससे शिप्रा का पानी भी स्वच्छ होगा और आगे चंबल, यमुना और गंगा साफ पानी के साथ बहेगी। प्रॉजेक्ट के तहत 13 किमी की पाइपलाइन भी डलेगी, जिसके पानी का उपयोग गार्डन, खेल मैदान, सड़क धुलाई में इसका उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में निगम

10 एसटीपी से 412 एमएलडी पानी प्रतिदिन उपचार कर रहा है। 90-90 एमएलडी के एसटीपी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। उनकी जगह नए बनेंगे। इनमें पानी पहले के मुकाबले ज्यादा शुद्ध होगा।

नर्मदा नदी इंदौर से 78 किमी दूर बहती है, लेकिन हमारी सरस्वती व कान्ह नदी गंगा बेसिन में आती है।

- कान्ह सांवेर होते हुए उज्जैन में शिप्रा में मिलती है
- महुिदपुर के पास पास चम्बल में मिल जाती है।
- इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है।
- यमुना प्रयागराज में गंगा में मिलती है।

यद्दु खेँ! बिना टेटी के नल
व्यर्थ बहते हैं बहुमूल्य जल



कान्ह में हैं कितनी नदियाँ? किसी को नहीं पता!

कान्हा, सरस्वती व उसकी 11 सहायक नदियों के शुद्धिकरण और उन्हें मूल स्वरूप में लाने के लिए 2014 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में प्रकरण चल रहा है। इस पूरे समय में एनजीटी ने निगम के जो आदेश दिए हैं, उनमें से एक भी धरातल पर नहीं उतर पाया है।

एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक निगम को इसका गूगल मैप निकालकर खसरा मैप से मिलान करना था। इस मैप से यह तय होना था कि कान्ह की दूरी कितनी है और इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं। निगम ने पहले एनजीटी को बताया कि सरस्वती और कान्ह दो नदियाँ हैं। फिर कहा कि आठ नदियाँ सहायक हैं। जबकि हकीकत यह है कि राऊ की पहाड़ी से सरस्वती और रालामंडल की पहाड़ी से कान्ह नदी निकलती है। कृष्णपुरा की छत्री पर इनका मिलन है। वहीं कान्ह और सरस्वती की 11 अन्य सहायक नदियाँ भी हैं। यह नदियाँ पीपल्या पाला तालाब, मूसाखेड़ी, खजराना तालाब, सिरपुर तालाब, सुखनिवास तालाब, गाँधीनगर, बिलावली तालाब जैसी जगहों से निकलती हैं।

इन नदियों के उद्गम स्थलों पर जानकारी पट्टिकाएँ लगाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके।

अतिक्रमण से घिरे हमारे तालाब

तालाब	क्षेत्रफल हेक्टेयर	ये है कब्जा
खजराना	3.137 हेक्टेयर	पूर्वी भाग में अतिक्रमण
बिलावली	102.741	दक्षिण में जीतनगर
बड़ा बिलावली	217.885 हेक्टेयर	झुग्गी बस्ती
श्रीराम	1.133, 5.990 हेक्टेयर	आंशिक अतिक्रमण
सिरपुर	95.9974 हेक्टेयर	ग्वाला कॉलोनी व प्रजापत नगर कच्चे व पक्के मकान
भौरासला	2.962 हेक्टेयर	--
लसूड़िया मोरी	4.478 हेक्टेयर	तालाब की भूमि पर शेड, भवन, स्कूल, सामुदायिक भवन
लिंबोदी	13.370 हेक्टेयर	अतिक्रमण
पीपल्याहाना	3.674 हेक्टेयर	अतिक्रमण
टिगरिया बादशाह	20.032 हेक्टेयर	15 मकानों का अतिक्रमण
कनाडिया	11.408 हेक्टेयर	अतिक्रमण
तलावली चांदा	13.688 हेक्टेयर	तालाब की जमीन पर मंदिर, टीनशेड, भेरूबाबा का चबूतरा, पट्टे के मकान
यशवंत सागर	524 मीटर आरएल	अतिक्रमण
उषापुरा	789.631 एकड़	अतिक्रमण

तालाब	क्षेत्रफल हेक्टेयर	ये है कब्जा
सिकंदरी	124.46 एकड़	अतिक्रमण
अंबाखेड़ी	315.451 एकड़	अतिक्रमण
गुलावट	257.259 एकड़	अतिक्रमण
लोंडिया, मुहम्मदपुर	20.023 एकड़	अतिक्रमण
सिंगावदा	124.197 एकड़	अतिक्रमण
बोरसी	51.713 एकड़	अतिक्रमण
बड़ी कलमेर	196.991 एकड़	अतिक्रमण
हिंगोनिया जागीर	11.784 एकड़	अतिक्रमण
माली बड़ोदिया	18.006 एकड़	अतिक्रमण
रोजड़ी	11.468 एकड़	अतिक्रमण
गुरदाखेड़ी	145.418 एकड़	अतिक्रमण
हातोद	76.912 एकड़	अतिक्रमण
फूल कराडिया	323.812 एकड़	अतिक्रमण
खजुरिया	667.745 एकड़	अतिक्रमण

शहरी सीमा में 28 छोटे-बड़े तालाब हैं, इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। यदि ऐसा कर पाए तो धरोहर बचने के साथ पानी का संवर्धन भी होगा।

हमारे शहर में भी है रामसर साइट;

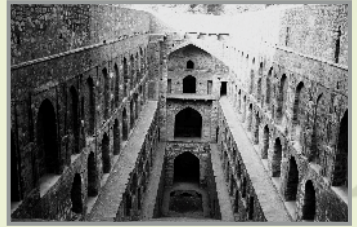
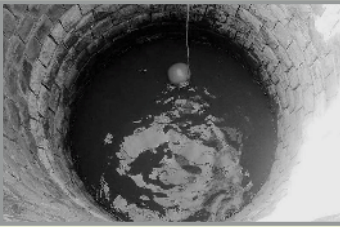
सिरपुर तालाब के बाद अब यशवंत सागर भी रामसर साइट बन गया है। 3 अगस्त को सिरपुर तालाब को यह दर्जा मिला था। शनिवार को देश के 11 वेटलैंड को पर्यावरणीय विशेषताओं के चलते 'रामसर साइट' की मान्यता दी गई। इंदौर मध्य भारत का पहला व देश का दूसरा जिला है, जहाँ दो तालाबों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। इससे यशवंत सागर विश्व धरोहर बन गया है। इसे न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बल्कि वैश्विक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय से इन तालाबों को यह मान्यता दिलवाने के प्रयास किए जा रहे थे।

रामसर साइट; 6 बड़े फ़ायदे

- अतिक्रमण पर पाबंदी
- मछुआरों की सीमाओं का सुनिश्चिय
- गंदगी से निजात - जैव विविधता को बढ़ावा
- पक्षियों के संरक्षण के लिए
नई प्रजातियों का पौधारोपण
- पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था रखना होगी
- किसानों का प्रशिक्षण जिससे केमिकल्स (कीटनाशी) का उपयोग न हो

हमारी धरोहर... कुएँ और बावड़ियाँ

- जीडीसी कॉलेज परिसर
- बड़ी गंगा बगीची
- कालानी नगर टंकी के पास
- मल्हारगंज बावड़ी
- रामबाग किबे साहब बावड़ी
- मीरा दातार बावड़ी
- महूनाका कब्रिस्तान
- सिरपुर
- विष्णुपुरी बड़ा कुआँ
- पीपल्या पाला
- फूटा पाला
- बिलावली कुआँ
- बाबा की दरगाह संवादनगर
- वंदना नगर सी-सेक्टर
- टेलीफोन नगर
- गीता चौक पाटनीपुरा
- मालवा मिल पक्की चाल
- न्यू पलासिया
हरिजन कॉलोनी
- सुखलिया
- बजरंग नगर गीता बावड़ी
- मेघदूत नगर
- बक्षीबाग बावड़ी



खत्म हुए...

850 कुएँ - बावड़ी

शहर का वर्तमान विकास चिंता में डालने वाला है। 40 साल में 850 कुएँ-बावड़ी कैसे समाप्त हो गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

हैरत की बात है कि वर्ष 1982 में शहर में 1400 कुएँ-बावड़ी निगम के रेकॉर्ड में थे, जिनकी संख्या 2023 में 550 रह गई है।

वर्षा जल को छत से, शूमि में रिसित करें
वर्षा शर मलकूप से अपने मटके भरें





भागते हुए लोग
जल्दी-जल्दी में
भर-भरकर रख रहे हैं
धूप को
हवा को
मिट्टी को
कल शायद कम न पड़ जाएँ
कल अकाल पड़ेगा
धूप
हवा और
मिट्टी का।

-वंदना पराशर



हरियाली

जैव विविधता में राजधानी से बेहतर हैं हम

म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वन्यजीव संस्थान, देहरादून और इकली साउथ एशिया के साथ भोपाल-इंदौर का शहरी जैव विविधता सूचकांक तैयार किया है। इसके लिए 23 इंडिकेटर्स तय थे। भोपाल को 92 में 44 और इंदौर को 35 अंक मिले।

प्रदेश में पहली बार किसी शहर का जैव-विविधता सूचकांक बनाया गया है। भोपाल में 79 तो इंदौर में 21 वर्ग किमी में हरियाली रिपोर्ट के अनुसार भोपाल को हरियाली के लिए 4 में 3 और इंदौर को 2 अंक मिले। 411 वर्ग किमी में फैले भोपाल में 79 वर्ग किमी में हरियाली है। 279.13 वर्ग किमी में फैले इंदौर में 21.25 वर्ग किमी में ही हरित क्षेत्र है।

प्रवासी पक्षियों में वृद्धि

भोपाल-इंदौर के वेटलैंड में स्थानीय पक्षियों की संख्या अच्छी मिली। इंदौर में 87, भोपाल में 115 प्रजातियाँ मिलीं। इसलिए दोनों शहरों को पूरे 4 अंक मिले।

पुराने आंकड़ों पर ही अटका है नगर निगम

मास्टर प्लान के अनुसार शहर में 21 फीसदी हरियाली होना चाहिए, लेकिन शहर में इसका उल्टा हो रहा है। कुछ समय पहले तक 13 फीसदी हरित क्षेत्र था, जो अब घटकर 7 प्रतिशत पर सिमट कर रह गया है। इसके बाद भी निगम सहित तमाम ज़िम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं है। उन्हें यही पता नहीं है कि वास्तव में शहर में कितने बगीचे और ग्रीन बेल्ट हैं। वे अब भी पुराने आंकड़ों पर अटके हैं।

यह तथ्य विकास दृष्टि भिन्न 2050 द्वारा निगम को दिए गए एक प्रेज़ेंटेशन में उभरकर सामने आया। पर्यावरण के रखवाले किशोर कोडवानी द्वारा पेश इस प्रेज़ेंटेशन में शहर की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शहर में उजाड़ पड़े हरित क्षेत्र, रीजनल पार्क व बगीचों को हरा-भरा कर के हरियाली का प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

1056 बगीचे

निगम अफसरों ने बताया शहर में निगम के रिकॉर्ड में 1056 बगीचे दर्ज हैं। इसमें से 400 बगीचों को हरा-भरा बनाने का काम निगम बीते 15 सालों में कर चुका है। इस पर पर्यावरण सचेतक किशोर कोडवानी ने बताया, यह आँकड़ा पुराना हो चुका है। अब नई कॉलोनियाँ बनी हैं, 29 गाँव नए जोड़े गए हैं। 1600 से ज्यादा कॉलोनियाँ हैं। ऐसे में शहर के हरित क्षेत्र और बगीचों की संख्या भी अधिक होगी। प्रशासन और निगम की नज़र से बचे रहने के कारण इन पर अतिक्रमण होता जाता है। धीरे-धीरे यह बगीचे आबादी में बदल जाते हैं।

हरित क्षेत्र के लिए निगम के दावे

1056 बगीचे निगम के रिकॉर्ड में 400 बगीचों के निर्माण का दावा कर रहा निगम जबकि 50 प्रतिशत से ज्यादा का रखरखाव कर रहे रहवासी संघ। 39 लाख आबादी जिले की, निगम प्रशासन का दावा, शहर में 25 लाख।

ऐसे बनना थे अहिल्या वन जो नहीं बने

योजना के अनुसार अहिल्या वन में बारिश को आकर्षित करने वाले पौधे लगाए जाने थे। पक्षियों के छोटे कुंड व नागरिकों के लिए ईको फ्रेंडली हट बनाने की योजना थी। फूलदार पौधे के साथ वानिकी प्रजाति लगाना थे। वरिष्ठ नागरिकों एवं छोटे बच्चों के लिए 1.5 से 2.5 मीटर चौड़े मुरम से निर्मित प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की जानी थी।



अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ,
पक्षियों के बसेरे नष्ट होने से बचाएँ

विकास के नाम पर हरियाली के साथ अत्याचार

नगर निगम ने एक साल पहले 2022-2023 के बजट में उद्यान विभाग के बजट को 12 से बढ़ाकर 181 करोड़ कर दिया। जिसका उद्देश्य शहर में 400 अहिल्या वन बनाने के साथ ग्रीन बेल्ट विस्तार कर हरियाली बढ़ाना था। बजट में घोषण यह भी की गई कि शहर के 35 वार्डों में इसके लिए ज़मीनें खोज ली जाएगी। शुरुआत में तेज गति से वन निर्माण की दिशा में काम हुआ। 10 स्थानों पर ज़मीन का चयन भी कर लिया गया। सितम्बर माह में 400 अहिल्या वन बनाने का लक्ष्य पूरा होता नहीं देख, वन निर्माण की संख्या एक तिहाई कर दी गई। मतलब निगम ने 100 स्थानों पर अहिल्या वन बनाने का निर्णय लिया लेकिन इस पर नगर निगम काम नहीं कर सका।



शहर में निरंतर घटती हरियाली

शहर में विकास के नाम पर फ्लाईओवर, ब्रिज, सड़क और मेट्रो निर्माण के लिए लगभग 15 हजार पेड़ काटे गए। पिछले पाँच सालों में लगभग 30 हजार पेड़ काटे गए हैं। वहीं विभिन्न निर्माण एजेंसियों ने सभी पेड़ों को 80 प्रतिशत ट्रांसप्लांट करने का दावा किया है।

बीते दिनों खजराना, लव-कुश चौराहा ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़ काटे गए, वर्तमान में फूटी कोठी, भँवरकुआँ ब्रिज के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण

- * ठूठ हरे भरे फैलाव वाले पेड़ों का विकल्प नहीं हो सकता।
- * काटने के बजाए बचाने की सोचें।
- * काटते पेड़ है लगाते पौधे।
- * विशेषज्ञों के अनुसार एक बरगद, पीपल का पेड़ लगभग 5000 से 7000 पौधों के बराबर होता है।

शहर की हकीकत

1982 में ही 21 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गई थी हरियाली। हरियाली महोत्सव के बावजूद शहर में केवल 7 प्रतिशत हरित क्षेत्र ही रह गए हैं।

खुरपी लाओ पौधे रोपो

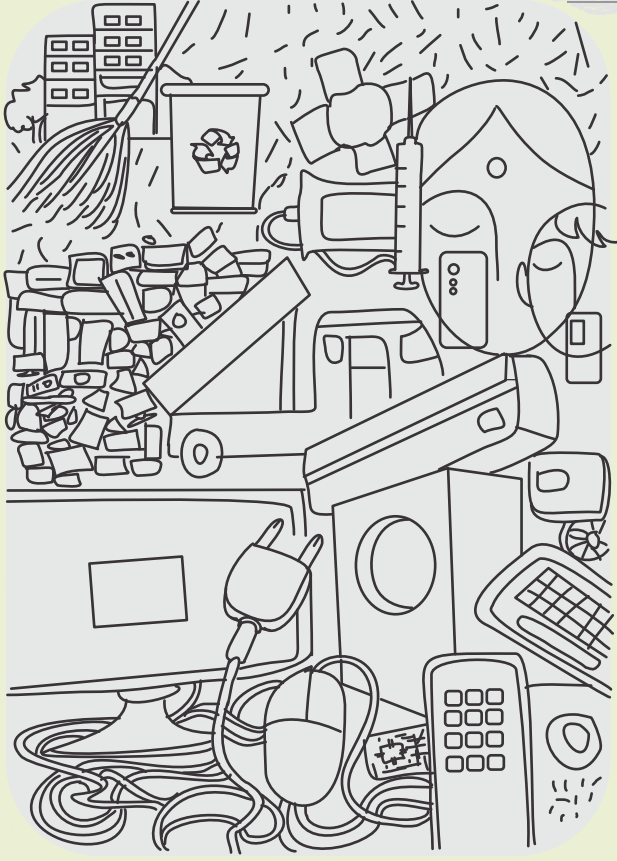
काट लिया सब
कुछ तो सौंपो ।
खुरपी लाओ
पौधे रोपो ।

ये पौधे जब, कल फल देंगे,
धरती को उर्वर जल देंगे ।
जब ये जीवन को तारेंगे,
जब बादल को ललकारेंगे,
नदियाँ तुमको क्षमा करेंगीं ।
सदियाँ तुमको क्षमा करेंगीं ।

छीन लिया सब
कुछ तो सौंपो ।
पौधे रोपो
पौधे रोपो ।



-सरोजकुमार



स्वच्छता

ई-कचरे का प्रतिशत

ई-वेस्ट निपटारे की हालत खरता :

देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नए-नए नवाचारों के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है। स्वच्छता व कचरे का निपटान देखने देश के कई शहरों का दल आ चुका है। यहाँ गीले-सूखे कचरे का निपटान तो अच्छे से हो रहा है लेकिन शहर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा परेशानी बनकर उभर रहा है। शहर में हर साल 20 से 30 फीसदी तक ई-कचरा बढ़ रहा है, जिसकी री-साइकिलिंग अफसरों के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रदेश के इंदौर व ग्वालियर में ही अधिकृत री-साइकिलिंग प्लांट हैं। यहाँ पर्यावरण के मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निपटान होता है। प्लांटों तक उनकी क्षमता से काफी कम ई-कचरा पहुँच रहा है। प्रदेशभर से हर साल 20 हज़ार मीट्रिक टन से ज़्यादा निकल रहे ई-वेस्ट का महज 25 फीसदी ही री-साइकिलिंग प्लांट्स तक पहुँच रहा है।

ई-वेस्ट के निपटान के लिए इंदौर में सबसे बड़ा री-साइकिलिंग प्लांट है। 6 हजार मीट्रिक टन क्षमता के प्लांट में अभी 500 मीट्रिक टन ई-वेस्ट का निपटान ही हो रहा है। इसमें ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि सामान अलग-अलग कर टेस्टिंग होती है। इसके बाद डिस्मेंटल की प्रक्रिया होती है। जोखिम भरे हेवी मेटल के निपटान में काफी सावधानी बरती जाती है। एक तरह से मेटल रिकवरी की प्रक्रिया होती है। इंदौर की बात करें तो यहाँ हर साल 5000 मीट्रिक टन तक ई-वेस्ट निकल रहा है। जो हर साल 20 से 30 फीसदी बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। इंदौर सहित उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, रीवा, चंबल में करीब 80 हजार मीट्रिक टन ई सामग्री है। इसका एक बड़ा हिस्सा हर साल ई-वेस्ट बन रहा है।

अस्पतालों में ठीक से नहीं हो रहा वेस्ट का निस्तारण

शहर के 200 छोटे (50 बेड से कम) अस्पतालों में नियमों के विपरीत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं हैं। ये अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। एसटीपी नहीं होने अस्पताल से निकलने वाला इन्फेक्टेड सीवरेज निगम की ड्रेनेज लाइन में मिल रहा है, जिससे बीमारियाँ फैलने का डर है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ के सदस्य डॉ. अफ़रोज़ अहमद के समक्ष यह रिपोर्ट रखी गई है।

एनजीटी सदस्य के निर्देश के बाद ज़िला प्रशासन ने शहर के साथ ग्रामीण अस्पतालों की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के आधार पर जाँच के आदेश दिए हैं। इन अस्पतालों के वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया चेक की जाएगी।

सरकारी महकमा कैसे जाँचें दुःप्रभाव

पर्यावरण विभाग के मामले की जांच के लिए टीम तो बना दी है, लेकिन विभाग के पास संसाधन सीमित हैं। पानी व मिट्टी में, एंटीबायोटिक अवशेष की जांच की सुविधा नहीं है।



रही कागज़ गलफर
नवजीवन जो पाए
हरे-शेरे वृक्षों को
फिर कटने से बचाए

ई-कचरे का प्रतिशत

टीवी 51 फीसदी, एयर कंडीशनर 21 फीसदी, रेफ्रीजरेटर 14 फीसदी, वाशिंग मशीन 09 फीसदी, कम्प्यूटर 26 फीसदी, फोन 02 फीसदी, टेलीफोन 01 फीसदी, एसी की 15 फीसदी हिस्सेदारी है।

नालियों में बहा रहे हैं मेडिकल वेस्ट

दवा की बोतलों को धोकर उन्हें फिर फार्मा कंपनियों को बेचने का फर्जीवाड़ा शहर पर भारी पड़ सकता है। एंटीबायोटिक के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे डॉ. डी.एस. चिटनीस अल्फा और बीटा इंडस्ट्रियल पार्क पहुँचे तो वे भी स्थिति देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आशंका जताई कि यह देश में लाखों मौतों के लिए ज़िम्मेदार, एंटीमाइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस (एएमआर) की गति को तेज़ कर सकता है। यानी एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने का खतरा है। यह 'सुपरबग' को निमंत्रण देने जैसा है। लांसेट जनरल के मुताबिक एएमआर से मरने वालों की संख्या एड्स व मलेरिया से मरने वालों की संख्या से अधिक है। अभी सालाना 12 लाख है जो 2050 तक एक करोड़ हो सकती है।

इन्हें नष्ट करना ही विकल्प

डॉ. डी.एस. चिटनीस कहते हैं कि खुले में पड़ी एंटीबायोटिक दवाएँ धोने के बाद बचा पानी नाले में बहाना ग़लत है। वेस्ट में मौजूद दवा जीवाणु व मानव मल में मौजूद बैक्टीरिया म्यूटेशन करते हैं। रोगों के कीटाणु पानी, दूध आदि के ज़रिए संक्रमण फैलाते हैं। कई रोगों को जन्म देने वाले एसचेरीचिया, सेलमोनीला, विब्रियो हेपेटाइटिस जैसे कीटाणु तब तक सक्रिय रहते हैं, जब तक उन्हें जलाकर नष्ट नहीं कर दिया जाता।

बायो मेडिकल वेस्ट नियम, 2016 मेडिकल वेस्ट के री-यूज़ की इजाजत नहीं देते। इससे गेस्ट्रिक प्रॉब्लम, एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, सी जैसे खतरे हैं।



एक वृक्ष भी बचा रहे...

अंतिम समय जब कोई नहीं जायेगा साथ
एक वृक्ष जायेगा
अपनी गौरियों-गिलहरियों से बिलुड़ कर
साथ जायेगा एक वृक्ष
अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले
'कितनी लकड़ी लगेगी ?'
श्मशान की टाल वाला पूछेगा
ग़रीब से ग़रीब भी सात मन तो लेता ही है !
लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में
कि बिजली के दाह घर में
हो मेरा संस्कार
ताकि मेरे बाद
एक बेटे और एक बेटी के साथ
एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में...

- नरेश सक्सेना



ध्वनि प्रदूषण

शोर के ज़ोर से बेहाल हमारा शहर

स्वच्छता में नंबर वन, वायु गुणवत्ता भी सुधार पर, लेकिन शहर में शोर का ज़ोर बहुत है। इसके सुधार के लिए भी तत्काल योजना बननी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण साइलेंस जोन में भी मानक या इससे ऊपर हो रहा है। शोर, अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सभी अधिकारी समन्वय से काम करें। ट्रैफिक व जिम्मेदार विभाग के सीनियर ऑफिसर खुद चौराहे पर खड़े होकर देखें। चेक करें, ध्वनि प्रदूषण कैसे हो रहा है? कार्रवाई करें, लोगों को समझाइश दें। प्रदूषण विभाग भी नियमित निगरानी और मापन करें।

अधिकारी ही ध्वनि प्रदूषण को कम करने की दिशा में भूमिका निभाएँ। किसी भी सुधार को लागू करने में इंदौर क्षमतावान है।

शोर प्रदूषण मात्रा डेसिबल में

मानक रहवासी क्षेत्र में दिन में 55
व रात में 45 साइलेंस जोन में
दिन में 50 व रात में 40 डेसिबल

शहर में औसत ध्वनि प्रदूषण

तय क्षेत्र	दिन	रात
रहवासी इलाके	46-73	42-67
व्यावसायिक	42-72	45-56
औद्योगिक	58-86	50-74
साइलेंस ज़ोन	44-69	40-58

ये हैं हॉट स्पॉट

क्षेत्र	दिन	रात
राजबाड़ा	65	43
रीगल तिराहा	63	44
पलासिया	65	48
बापट चौराहा	64	49
रेलवे स्टेशन	67	58
महू नाका	63	46
व्हाईट चर्च	63	42
एयरपोर्ट	60	61
सियागंज	64	47
पोलोग्राउंड	69	46
बंगाली चौराहा	65	43
आइटी पार्क	63	41
रेडिसन चौराहा	62	50
गंगवाल स्टैंड	64	51
लवकुश चौराहा	67	45

कल के लिए.... आज ही कुछ करना होगा

कटते पेड़,
प्रदूषित नदियाँ
काला धुआँ
अम्लीय गैसों
फैला प्लास्टिक
सड़ता कचरा
बढ़ती गर्मी
घटती वर्षा
दूषित वायु
उद्योग अपशिष्ट

परन्तु घुट-घुट कर
रोग पाल कर
दवाई खा कर
निभाएगी बस
जीने की औपचारिकता

इसलिए
सुनहरे कल के लिए
आज कुछ करना होगा
पर्यावरण को बचाना होगा ।

सभी कह रहे
चीख चीख कर
प्रगतिशील मानव से
सोचो कुछ तो
कहो मत केवल
करो कुछ तो
बचाओ हमें
ज़हर होने से
वरना अगली पीढ़ी
कोसेगी तुम्हें
ज़हरीले वातावरण में
वह जी तो लेगी



आपके घर, शोरूम या दफ़्तर के बाहर यदि कोई पेड़ मौजूद हो तो साफ़-सफ़ाई में काम आने वाला फ़िज़ूल पानी इन पेड़ों को अवश्य पिलाएँ

यदि आप अपने बगीचे के गमलों या क्यारी में पानी दे रहे हों तो थोड़ी सी प्यास उस पेड़ की भी बुझाएँ जो आपके परिसर के बाहर या नज़दीक मौजूद हो।

तेज़ सूरज में प्रकृति झुलस रही है। पेड़ बेचैन हैं। यदि थोड़ी सी सहृदयता मनुष्य दिखाए तो न जाने कितने गुना प्रेम यही पेड़ हमें लौटाते हैं। ऑक्सीज़न देते हैं, छाया देते हैं और बारिश लाते हैं।

पौधे हमारा परिवार हैं, यह बात परिवार के बच्चों को भी सिखाएँ और कार्यालय के सहकर्मियों को भी बताएँ। प्रकृति से अनुराग जताएँ।

तपती गर्मी में पेड़ों को पानी पिलाकर पुण्य कमाएँ



कल न रहेंगे 'मानव' हम

प्यारी सी नदियाँ बहती थीं ।
वृक्ष जहाँ झूमते रहते थे ।
आज वहाँ कंकर पत्थर हैं
वृक्ष बदल गए आज ढूँठ में
हर मानव के कर्म हैं कैसे
आज नहीं समझते हम ।

कल न रहेगा सुरक्षित पर्यावरण
कल न रहेंगे 'मानव' हम ।

-आशुतोष सिंह गौर



आभार

- उन सभी प्रकाशनों का जिनके समाचारों और आलेखों से हमें पर्यावरण पर एकाग्र महत्वपूर्ण सामग्री मिली
- सभी कवियों का जिनकी रचनाएँ हम इस पुस्तिका में संकलित कर पाए

इन्दौर में सेवा-सुरभि के प्रमुख वृक्षारोपण प्रकल्प

- ❖ सपना संगीता रोड
- ❖ नवलखा-अग्रसेन प्रतिमा मार्ग
- ❖ बॉम्बे हॉस्पिटल-सत्य साईं मार्ग
- ❖ अहिल्याश्रम से रामकृष्ण आश्रम वीआईपी रोड
- ❖ ग्रीन पार्क (हाईकोर्ट-एलआईसी) एम.जी. रोड
- ❖ यशवंत निवास रोड
- ❖ गंगा वाटिका, श्रीराम मंदिर पंचकुइया परिसर





देश की माटी देश का जल
हवा देश की देश के फल
सरस बनें प्रभु सरस बनें ।
देश के घर और देश के घाट
देश के वन और देश के बाट
सरल बनें प्रभु सरल बनें ।
देश के तन और देश के मन
देश के घर के भाई बहन
विमल बनें प्रभु विमल बनें ।

काव्य-पंक्ति : गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर - अनुवाद : पं. भवानीप्रसाद मिश्र

रूपांकन एवं मुद्रण : एडराग एडवर्टाईजिंग, इन्दौर - मोबाइल : 9752526881